(b) and (c). An increase in the purchasing power of the Rupee is synonymous with a reduction in the price level and all Government policies are geared towards achieving that objective.

आयकर अधिकारियों द्वारा मारा गया छापा

3642. **श्री अम्बिका प्रसाद पांडेय :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनीतिक द्वेष भावना से आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों के बारे में सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या बांदा जिले में अग्रवाल नर्सिंग होम के मालिक डा० चूड़ामणि अग्रवाल के यहां आयकर विभाग द्वारा मारे गये छापों के बारे में अप्रैल 1977 में दिये गये अभ्यावेदन पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकार ने एक जांच आयोग नियुक्त किया है, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने प्राधिकार के किये गये दुरुपयोग ज्यादतियों तथा अनैतिक चलनों की और ऐसे अन्य व्यक्तियों की जांच करेगा, जिन्होंने आपात स्थिति की घोषणा के लागू रहने की अवधि अथवा इससे तत्काल पूर्ववर्ती अवधि के दौरान इस प्रकार के कार्य करने के लिये निदेश दिये हैं, अवप्रेरित किया हो अथवा उसमें अन्य किसी प्रकार का सहयोग दिया हो। यदि असंगत कारणों से कोई छापे मारे गये हों, तो वे उक्त आयोग की अधिकार सीमा के अंतर्गत आयेंगे।

(ख) जो परिसम्पत्तियां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132(5) के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश द्वारा रोक ली गयी हैं, उन को छोडकर शेष सभी परिसम्पत्तियां छोड दी गई हैं। उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध कर-निर्धारितों द्वारा किये गये आवेदन के सिलसिले में आयकर आयुक्त आगरा ने 25 जुलाई, 1977 को सुनवाई निश्चित की है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में जिला शाखा गिरिडीह में काम करने वाले डाक-कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

3643. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 50 हजार या उस से अधिक आबादी वाले नगरों में कार्यरत अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देती है ;

(ख) यदि हां, तो जिला शाखा गिरिडीह (बिहार) में कार्यरत डाक कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता न देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में उन कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते की अदायगी के विद्यमान आदेशों के अधीन, नगरपालिका का दर्जा रखने

वाला कस्बा, जिसकी 1971 की जनगणना के अनुसार कम से कम आबादी 50,000 हो, वहां पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते की अदायगी के लिये वर्गीकरण किये जाने योग्य होता है।

(ख) 1971 की जनगणना के अनुसार गिरिडीह की आबादी केवल 40,308 है और वह वहां पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्तों के प्रयोजन के लिये, वर्गीकरण किये जाने योग्य नहीं है।

(ग) जी हां।

विदेशी ऋण

3644. **श्री हुक्म देव नारायण यादव : (मधुबनी)**: क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी ऋणों पर, देशवार, ब्याज की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण की राशि कितनी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) महोदय आज की तारीख की स्थिति यह है कि भारत सरकार ने विदेशी ऋणों के ब्याज की कोई भी देय और बकाया रकम नहीं देनी है। किन्तु भारत सरकार को प्राप्त विदेशी ऋणों पर 1977-78 के दौरान देय ब्याज की अनुमानित रकम का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जनसंख्या पूर्वानुमान विषयक विशेषज्ञ समिति द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार पहली मार्च, 1977 को भारत की जनसंख्या के आधार पर, 31 मार्च, 1977 को भारत सरकार के नाम बकाया विदेशी ऋणों की प्रति व्यक्ति रकम 138.49 रुपये बैठती है।

विवरण

क्रम सं०	देश/स्त्रोत का नाम	रकम
1.	आस्ट्रिया	0.96
2.	बेल्जियम	0.68
3.	कनाडा	3.49
4.	डेनमार्क	0.06
5.	फ्रांस	13.03
6.	जर्मन संघीय गणराज्य	33.98
7.	इटली	0.52
8.	जापान	29.85
9.	नीदरलैण्ड	6.98
10.	स्वीडन	0.88